214 लोगों को उत्तराखंड में बुधवार को गिरफ्तार किया गया है लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर। यहां पिछले 10 दिनों में 2524 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2449 वाहन सीज किए गए हैं।

चिकित्साकर्मियों को डब्ल्यूएचओ मान्य सुरक्षा किट पर सरकार से जवाब तलब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नागपुर के डॉक्टर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अर्जेंट सुनवाई
- सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर कोर्ट ने औपचारिक नोटिस नहीं किया जारी

सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गंभीर परिस्थितियों में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्साकर्मी को विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा मान्य सुरक्षा किट और उपकरण उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ नागपुर डॉक्टर जेरेल बैनेट की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रही थी। पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अगले हफ्ते तक जवाब देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर कोई औपचारिक नोटिस नहीं जारी किया है।

याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्साकर्मी बहुत ही खतरनाक और गंभीर परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए। डॉक्टरों, नर्सों व अन्य चिकित्साकर्मियों को डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्य सुरक्षा किट जैसे सुरक्षा सूट व अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मेहता ने पीठ से कहा कि कोर्ट इस याचिका पर फिलहाल कोई नोटिस जारी न करे वे स्वयं मामले को देखेंगे। मेहता ने कहा कि एक दिन पहले भी ऐसी एक याचिका आई थी। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह याचिका की कापी सॉलिसिटर जनरल को दें।

पीपीई पर पीआइएल दाखिल : सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों के साथ ही सुरक्षाकर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर भी एक जनहित याचिका (पीआइएल) दायर की गई है। इसमें केंद्र के साथ ही सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वो अपने यहां पीपीई की कमी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करें।

मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने की मांग पर नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के चलते मास्क व सैनिटाइजर को तय कीमत पर ही बेचे जाने और इन चीजों की कालाबाजारी रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र को तीन अप्रैल तक जवाब देना है। मामले पर तीन अप्रैल को फिर सुनवाई होगी।

कोर्ट ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मामले पर तत्काल सुनवाई की। यह याचिका जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष सत्यम सिंह ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते मास्क और सैनिटाइजर जरूरी वस्तुओं में आते हैं। सरकार ने जरूरी वस्तु कानून के तहत उनकी कीमतें तय कर दी हैं ऐसे में उनकी बिक्री उन्हीं कीमतों पर सुनिश्चित कराई जाए और मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकी जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त में बंटा जाए। इसके लिए जगह-जगह वितरण केंद्र स्थापित किए जाएं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को ये चीजें निर्धारित कीमत पर नहीं मिलती और दुकानदार ज्यादा कीमत मांगता है तो व्यक्ति उनकी संस्था की वेबसाइट पर सूचित कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमत का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की जरूरत है ताकि इस मुश्किल समय में लोगों को सही कीमत पर ये चीजें उपलब्ध हो सकें।

वित्तीय आपातकाल की मांग पर शीर्ष अदालत ने नहीं दिया कोई आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में समान व्यवस्था लाने के लिए वित्तीय आपातकाल लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कुछ देर बहस सुनने के बाद मामले की सुनवाई अदालत के नियमित कामकाज शुरू होने तक स्थगित कर दी।

सेंटर फॉर अकाउंटैबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (सीएएससी) संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से कोरोना महामारी के चलते देश में पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 360 (3) के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की मांग की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मामले पर सुनवाई की। वकील विराग गुप्ता ने याचिका पर पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना संकट के चलते पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जो भी आदेश जारी कर रही है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 360 (3) के तहत जारी किया जाए। इस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। ऐसा करने से केंद्र के आदेश राज्यों पर बाध्यकारी होंगे।

पीठ विराग गुप्ता के तर्कों से बहुत सहमत नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि वे जो बातें कहना चाहते हैं, उसके बारे में सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। वकील ने कहा कि कोर्ट उनकी याचिका को ज्ञापन की तरह सरकार को भेज दे। बाद में कोर्ट ने बगैर कोई आदेश दिए मामले की सुनवाई तबतक स्थगित कर दी, जबतक कि अदालत का कामकाज सामान्य नहीं हो जाता।

बाबा साहब और जगजीवन राम जयंती के कार्यक्रम स्थगित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर और बाबू जगजीवन राम की जयंती पर होने वाले आयोजनों को स्थगित कर दिया है। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं से भी भीड़-भाड़ वाले आयोजनों से परहेज करने को कहा है। सरकार ने यह फैसला तब लिया है, जब इसी माह पांच अप्रैल को बाबू जगजीवन राम और 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है। खास बात यह है कि इस आयोजनों को धूमधाम से मनाने के लिए सरकार की ओर से हर साल निजी संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय मदद भी दी जाती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने लोगों से इस मौके पर भीड़भाड़ भरे आयोजन न करने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि सभी लोग घर पर रहकर ही बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को इस पर गंभीरता से अमल करने को कहा है। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआइ) देश भर में बाबा साहब के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित करती है। आंबेडकर फाउंडेशन व बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, कोरोना संक्रमण के चलते गृह मंत्रालय की ओर जारी एडवाइजरी को देखते हुए जयंती पर बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है।

कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए सेना तैनात करेगी 8,500 डॉक्टर

रणनीति ▶ सैन्य प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की समीक्षा बैठक

अपने अस्पतालों के नौ हजार बेड भी वायरस से पीड़ित लोगों के लिए किए आरक्षित

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देखकर सेना ने अपने 8,500 से अधिक डॉक्टरों व चिकित्साकर्मियों को इस संक्रमण से निपटने के काम में लगा दिया है। साथ ही अपने अस्पतालों के नौ हजार से अधिक बेड भी केवल कोरोना पीड़ितों के लिए रखे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बुधवार को इस वैश्विक महामारी से मुकाबले के लिए कई गई तैयारियों की समीक्षा के बाद अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की मदद के लिए 25 हजार से अधिक एनसीसी कैडेटों को भी बतौर स्वयंसेवकों तैनात किया जा रहा है। ऐसा संक्रमण से प्रभावित लोगों की तादाद के बढ़ते जाने के चलते किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिये सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों के योगदान की गहन समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सिंह ने इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं को नागरिक प्रशासन की मदद को दोगुना करने को कहा है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और संगठनों से तालमेल बढ़ाकर इस दिशा में हर कठिनाई को दूर करने को कहा है। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने और रक्षा सचिव अजय कुमार समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में जनरल रावत ने कहा कि कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए अलग अस्पतालों की व्यवस्था की गई है। इसमें 9 हजार से अधिक बेड होंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने से कोरोना वायरस के रोकने के उपायों पर चर्चा की। एएनआइ

जनरल नरवाने ने रक्षामंत्री को बताया कि 8500 से अधिक डॉक्टर और चिकित्सा स्टाफ को केवल कोरोना पीड़ितों के इलाज में लगाया जाएगा। यह लोग नागरिक प्रशासन की पूरी सहायता करेंगे।

इसी तरह नौसेना प्रमुख ने बताया कि जरूरत पड़ने पर स्टैंडबाइ के तौर पर नौसैनिक जहाज भी तैयार रखे गए हैं। स्थानीय प्रशासन की नौसेना भी सहायता कर रही है। वायुसेना के मुखिया एयरचीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने चिकित्सकी वस्तुओं और उपकरणों की आपात आपूर्ति के लिए पिछले पांच दिनों से कई विमान तैयार रखे हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने बताया कि संगठन ने वेंटिलेटर में मामूली बदलाव करके उसे एक मशीन में एक ही समय में चार मरीजों की देखरेख की व्यवस्था की है। सुरक्षा बलों के लिए 1.5 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाया है। पांच लेयर वाले दस हजार मास्क तैयार किए हैं। जल्द ही 20 हजार मास्क और तैयार किए जाएंगे।

कोरोना पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लॉकडाउन के बाद पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी बैठक
- इससे पहले 20 मार्च को भी पीएम ने की थी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल

कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का एक हफ्ता बीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। माना जा रहा है कि गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली बैठक में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की मौजूदा स्थिति, विभिन्न राज्यों में फंसे घर लौट रहे लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों के साथ-साथ तब्लीगी जमात के लोगों के विभिन्न राज्यों में जाने से उत्पन्न खतरे पर भी चर्चा होगी।

लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। इससे पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दो दिन पहले 20 मार्च को प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। उस समय उन्होंने कोरोना के वैश्विक खतरे के प्रति मुख्यमंत्रियों को आगाह करते हुए पूरे देश को एकजुट होकर इसका सामना करने की जरूरत बताई थी। 24 मार्च की मध्य रात्रि से पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्यों को घर-गांव लौट रहे लोगों से लेकर कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। वैसे कैबिनेट सचिव और गृह सचिव लगातार राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बातचीत कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही स्थिति से निपटने के लिए हर दिन नए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में राजनीतिक नेतृत्व की एकजुटता ज्यादा जरूरी है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली यह बैठक अहम मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ एकजुटता दिखाते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। उम्मीद है कि सभी मुख्यमंत्री पिछले एक हफ्ते के लॉकडाउन के अपने अनुभवों को साझा करते हुए राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों को भी प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे।

भारत-चीन के बीच राजनयिक रिश्तों के 70 वर्ष पूरे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम मोदी और राष्ट्रपति चिनफिंग ने दिए बधाई संदेश, कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा समारोहों का आयोजन

भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों को 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोनों देशों ने पहली अप्रैल, 2020 को कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने एक-दूसरे को बधाई दी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी एक-दूसरे को संदेश भेजा। हालांकि कोरोना संकट के चलते इस वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर असर दिख रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच चेन्नई के मामल्लपुरम में हुई मुलाकात में इस वर्षगांठ के मौके पर 70 तरह के कार्यक्रमों के आयोजन पर सहमित बनी थी। मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग को भेजे संदेश में लिखा, भारत-चीन सिर्फ दो पुरानी सभ्यताएं ही नहीं हैं बल्कि एक-दूसरे को मदद करने का हमारा काफी लंबा इतिहास रहा है। आज हम दोनों दो बड़े विकासशील देश हैं जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण रिश्ते इस क्षेत्र व समूचे विश्व में शांति व सद्भाव के लिए जरूरी हैं। मोदी ने कहा, कोविड-19 के कारण आज दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है और हमें इसका सामना करने के लिए सही मायने में वैश्विक रणनीति बनानी चाहिए। मोदी ने कहा, वह दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी को बधाई संदेश भेजा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे संदेश में कहा, दोनों देशों ने 70 वर्षों में ऐतिहासिक रास्ता तय किया है। शांति व विकास के साथ एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और तेज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वह भारत के साथ रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और इस रिश्ते को नई मंजिल की तरफ ले जाने को तैयार हैं।

अस्पताल से लेकर आर्थिक मोर्चे के इंतजामों ने खोला आगे का रास्ता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सरकार की तरफ से 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया गया एलान
- आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए अलग तंत्र बना
- मजदूरों-कामगारों को रोकने के लिए की गई कई घोषणाएं
- नकदी के इस्तेमाल को कम करने के लिए ई-ट्रांजेक्शन चार्ज खत्म किया गया

पिछले एक सप्ताह में सरकार की तरफ से किए गए व्यापक इंतजाम की बदौलत ही लॉकडाउन के आगे का रास्ता कामयाबी की ओर बढ़ता दिख रहा है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार ने अस्पताल लेकर आर्थिक मोर्चे पर कई व्यापक इंतजाम किए। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई निर्बाध गति से जारी रखने के लिए एक अलग तंत्र विकसित किया गया। श्रमिकों को घर लौटने से रोकने के लिए उन्हें हर प्रकार की मदद का भरोसा दिया गया और उस दिशा में कई घोषणाएं की गईं। हालांकि, इस दौरान कुछ मजदूर, कामगार और छोटी-छोटी कंपनियों के कर्मचारी अपने घरों को भी लौटे।

लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ सभी जरूरी सामान के विक्रेताओं को विशेष छूट दी गई। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के दौरान भी प्रसार-प्रचार के माध्यम से एक प्रणाली विकसित की गई ताकि संपर्क से होने वाली इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। नकदी के कम से कम इस्तेमाल के लिए ई-ट्रांजेक्शन के चार्ज को समाप्त किया गया और सीमित तरीके से बैंकिंग प्रणाली को जारी रखा गया।

सरकार ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कई नियम बदल डाले तो 31 मार्च को समाप्त होने वाले कई नियमों की तारीख को तीन महीने का विस्तार दे दिया। इनमें इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी रिटर्न तक शामिल है। कंपनियों को अपने कार्यकलापों के लिए समय सीमा में विस्तार दे दिया गया। महामारी से लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर के पर्याप्त इंतजाम के साथ 22 लाख स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के लिए 50-50 लाख रुपए के इंश्योरेंस की घोषणा की गई, ताकि उनका मनोबल कायम रहे। श्रमिकों को घर लौटने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से सामूहिक स्तर पर खाने-रहने की व्यवस्था की गई ताकि आगामी 14 अप्रैल तक दिहाड़ी मजदूर अपना जीवनयापन कर सकें । सभी गरीबों को तीन-तीन महीने के लिए मुफ्त में चावल-दाल और गेहूं देने की घोषणा की गई। खाना बनाने के लिए मुफ्त में गैस सिलेंडर देने के साथ उनके खाते में 500-500 रुपए भी देने का एलान किया गया। इन सब के लिए सरकार की तरफ से 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का एलान किया गया। लोगों को घरों तक सीमित रखने के लिए पुलिसिया अंदाज को बिल्कुल नए कलेवर में पेश किया गया। रौब के लिए मशहूर पुलिस वाले जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की मदद के लिए तत्पर दिख रहे हैं।

जेईई-एडवांस्ड की परीक्षा टली

- मौजूदा हालात को देखते हुए टाली गई परीक्षा, 17 मई को देशभर में होना था आयोजन

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों में देश की 23 आइआइटी के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई-एडवांस्ड को फिलहाल टाल दिया गया है। आइआइटी दिल्ली के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह परीक्षा 17 मई को आयोजित होनी थी। कोरोना के कारण जेईई-मेन की परीक्षा को पहले ही टाला जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए जेईई-एडवांस्ड की परीक्षा को टाल दिया गया है। इस परीक्षा की नई तारीख जेईई-मेन की तारीख निश्चित होने के बाद तय होगी। जेईई-मेन का आयोजन देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए किया जाता है। इसे जेईई-एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग एक्जाम भी माना जाता है। जेईई-मेन का आयोजन मई के आखिरी सप्ताह मे होने की बात कही गई है।

प्लेसमेंट पर असर न पड़ने दें : निशंक : इस बीच, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश की विभिन्न आइआइटी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोरोना के कारण छात्रों के प्लेसमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। 23 आइआइटी प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में निशंक ने इस संबंध में टास्क फोर्स बनाने का भी निर्देश दिया।

निशंक ने कहा, 'यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोरोना के चलते इस साल होने वाला प्लेसमेंट पिछले वर्षों की तुलना में कम नहीं हो। इस संबंध में कंपनियों से बात करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा सकता है। संस्थानों के अकादमिक कैलेंडर भी इस तरह से तैयार किए जाने चाहिए ताकि छात्रों को समर या विंटर इंटर्नशिप का नुकसान नहीं हो।' मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को भी संस्थान ध्यान में रखें। उन्होंने इस संबंध में हेल्पलाइन स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

विरोध

चिदंबरम ने कहा- 30 जून तक बहाल की जाएं पुरानी दरें, कोरोना संकट में जीडीपी की चिंता के बजाय लोगों की जिंदगी बचाना अहम

बचत ब्याज दरें घटाने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पीपीएफ और एनएससी समेत तमाम सरकारी छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कटौती को वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि कोरोना से गहराए आर्थिक संकट में इन बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कटौती से आमलोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। साथ ही यह भी कहा है कि संकट के इस दौर में आर्थिक विकास की गति से ज्यादा अहम लोगों की जिंदगी बचाना है।

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने पीपीएफ, सुकन्या, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, एनसीसी समेत सभी सरकारी बचत योजनाओं के ब्याज दर में एक फीसद से अधिक तक की कटौती पर ट्वीट के जरिये प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर कम करना तकनीकी रूप से सही हो सकता है। पर मौजूदा वक्त ऐसा करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। उनके मुताबिक, अनिश्चित आय और गंभीर संकट के समय में लोग अपनी बचत पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर करते हैं। ऐसे में सरकार को तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और मौजूदा हालत को देखते हुए 30 जून तक पुरानी ब्याज दरों को बहाल करना चाहिए। सरकार पर कटाक्ष करते हुए चिदंबरम ने कहा, 'मुझे पता है कि कभी-कभी सरकार बेवकूफी भरी सलाह पर काम करती है, लेकिन मैं हैरान हूं कि यह सलाह कितनी बेवकूफी भरी है।' कोरोना और लॉकडाउन से बढ़ी आर्थिक चुनौतियों से वाकिफ होने का संकेत करते हुए चिदंबरम ने कहा, 'मेरे विचार में हमें अब विकास की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी कीमत फोकस लोगों के जीवन को बचाने पर होना चाहिए।' कोरोना की आर्थिक चुनौती के लिए राहत सहायता के 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए कांग्रेस नेता ने दो दिन पहले सरकार से दूसरे बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की थी। आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा नहीं करने के सरकार के रुख पर उन्होंने अपनी निराशा भी जताई।

पी चिदंबरम। फाइल

कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी प्रेस कांफ्रेंस कर ब्याज दरों के घटाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, इससे 30 करोड़ लोगों की बचत प्रभावित हुई है। इस कटौती से मध्यम वर्ग, पेंशनर, किसान, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक समेत सभी लोगों को मुश्किल होगी। वहीं, कपिल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यहां दो भारत हैं। एक में लोग घर में बैठकर योग कर रहे, अंताक्षरी खेल रहे और रामायण देख रहे हैं। दूसरे में लोग अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं।

भाजपा का जवाब, यह नियमित आलोचनाओं का समय नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार के फैसलों पर कांग्रेस की आलोचनाओं पर तंज करते हुए सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कहा कि यह रोजमर्रा के राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी का सबको एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने बुधवार को कहा कि जब कोरोना की वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए सबको एकजुट होने का समय आया है तो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की रोजमर्रा की आलोचना करने में व्यस्त है।

नलिन कोहली। फाइल

कह के रहेंगे माधव जोशी

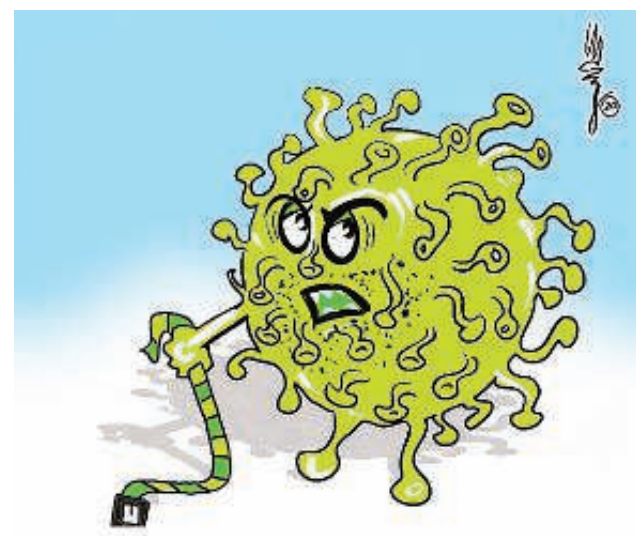

जमावड़ा लगाओगे तो मेरी ही जमात में आओगे!